

मोदी बोले- लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं : मंत्रियों से कहा- फालतू पेपरवर्क खत्म करें, नियम-कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हों

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि मैं फालतू पेपरवर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूँ। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार-बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं है। पीएम

ने यह बात संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग (एनडीए) की संसदीय दल की बैठक में मंत्रियों और सांसदों से कही। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार जीत के शिल्पकार हैं। सरकार ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन की इजाजत देकर नागरिकों पर भरोसा किया। इस बात पर जोर



दिया कि यह भरोसा बिना किसी गलत इस्तेमाल के 10 साल से कामयाबी से काम कर रहा है। ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ ड्रिंग बिजनेस दोनों ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है देश अब पूरी तरह से ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ फेज में है, जहां सुधार तेजी से और साफ इरादे से हो रहे हैं। सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं, न कि सिर्फ आर्थिक या रेवेन्यू-केंद्रित। इसका लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी

क्षमता तक बढ़ सकें। पीएम मोदी 11 दिसंबर को ह्द के सभी सांसदों के लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन करने वाले हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, समन्वय और संसद सत्र के दौरान साझा रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इस दिन में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रांट’ के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज की मदद से एक निवेशक- हितैषी वातावरण तैयार होगा, जिससे यहां 24 हजार 240 करोड़ रुपये के निवेश के रास्ते खुलेंगे। यह प्रयास सीधे तौर पर 29 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर आर्थिक उन्नयन का नया मार्ग खोलेगा। स्वीकृति अनुसार भूमि प्रबन्धन और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है और संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत



शुल्क में छूट दी गई है। वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे, जबकि एमएसएमई इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति-2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा सागर-दमोह मार्ग, लंबाई 76.680 किमी फोरलेन मय पेक्ड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण के लिए परियोजना वित्तीय लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार लागत का 40 प्रतिशत हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भू अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया

जाएगा। परियोजना अंतर्गत 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, एक आरओबी, 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा।

दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए नियमित और आउट सोर्स पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह, छतरपुर और बुधनी के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउट सोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउट सोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद द्वारा सागर में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सितंबर 2022 में कूनों राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास प्रारंभ किया गया है। कूनों राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 28 और गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर 02 चीतों का रहवास है।

बुंदेलखंड धरा है हीरों और महावीरों की : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड हीरों और महावीरों की धरती है। यह मंदिरों की नगरी है। उन्होंने कहा कि महाराज छत्रसाल के कार्य काल में बुंदेलखंड की महाविजय होती थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराज छत्रसाल के शौर्य को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल की प्रतिमा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का खजुराहो में अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव छतरपुर के राजनगर में लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि



आज प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को 1857 करोड़ रुपये राशि अंतरित की गई है। इनमें छतरपुर की 3 लाख 24 हजार से अधिक लाड़ली बहनों को शामिल हैं। हितग्राहियों बहनों को उनके बैंक खातों में 31वीं किस्त के रूप में 1500 रुपये की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अब तक 46 हजार 500

करोड़ की राशि बहनों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। बहनें अपने परिवार के संचालन में भी सहयोग कर रही हैं। बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहनों को पक्के मकान और उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुंदेलखंड के चहुँमुखी विकास के लिए 270 करोड़ लागत के 9 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 240 करोड़ लागत के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 2 सांदीपनि विद्यालय और स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं।

विशेष संपादकीय

विश्वनाथ समाचार - प्रवेशांक

प्रिय पाठकों,



संदीप परमार
संपादक
विश्वनाथ समाचार

अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि हम आज विश्वनाथ समाचार का प्रवेशांक आपके हाथों में सौंप रहे हैं। यह केवल एक समाचार नहीं, बल्कि विचारों, सत्य और सामाजिक जागरूकता का एक संकल्प है। हमारा लक्ष्य है— जनसरोकारों को केंद्र में रखकर निष्पक्ष, निर्भीक और तथ्याधारित पत्रकारिता को नई दिशा देना। आज के समय में जब सूचना की बाढ़ के बीच सही और विश्वसनीय खबरें ढूँढना चुनौती है, विश्वनाथ समाचार यह जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहा है कि हर पाठक तक संतुलित खबरें, सार्थक विश्लेषण और समाज को दिशा देने वाली सामग्री पहुँचे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम शासन-प्रशासन की गतिविधियों, जनहित के मुद्दों, सामाजिक सरोकारों, युवाओं की ऊर्जा, किसानों की चिंता और आमजन की आवाज को अपने पन्नों पर प्रमुखता दें। यह समाचार आपका मंच है—आपके विचार, आपकी समस्याएँ, आपकी उम्मीदें। हमारी टीम पाठकों की भागीदारी को सर्वोपरि मानती है और यही सहभागिता हमें निरंतर बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। हम आशा करते हैं कि विश्वनाथ समाचार सत्य, समर्पण और सार्थक पत्रकारिता की नई पहचान बनेगा। आपसे निवेदन है कि अपनी अमूल्य सुझावों और सहयोग से हमें सशक्त करते रहें।

नेशनल लोक अदालत : संवाद, मध्यस्थता और राजीनामा के माध्यम से त्वरित न्याय की अनूठी मिसाल है - जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान

13 दिसंबर 2025 को देपालपुर इंदौर जिले सहित समूचे मध्यप्रदेश व देश में पक्षकारों को मिलेगा सरल, सुलभ और सौहार्दपूर्ण समाधान

देपालपुर। तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने नेशनल लोक अदालत के आयोजन के बारे में बताते हुए कहा कि देशभर में आयोजित हो रही लोक अदालतों ने हमेशा यह साबित किया है कि जब न्याय प्रक्रिया में संवाद, समझाइश और मध्यस्थता को स्थान मिलता है, तो विवाद मुकदमों में नहीं, समाधान में बदल जाते हैं। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के निर्देशन में एवं तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश माननीय हिदायत उल्ला खान के मार्गदर्शन में देपालपुर सिविल न्यायालय सहित संपूर्ण देश में आयोजित होने वाली इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत संवाद, मध्यस्थता और आपसी राजीनामे के माध्यम से कई प्रकरणों का त्वरित, शांतिपूर्ण और संतोषजनक निराकरण कर पुनः समाज को यह सशक्त संदेश देने जा रही है कि न्याय केवल निर्णय नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का साधन भी है। तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के तत्वावधान में अधिवक्ता संघ के सहयोग एवं मध्यस्थता केन्द्र की सक्रिय



भूमिका और प्रशिक्षित मध्यस्थों, पैनल अधिवक्ताओं व पैरालीगल वॉलंटियर्स के प्रयासों से कई बिछड़े परिवारों को पुनः एक होने, कई आपसी विवादों के समाप्त होने और पक्षकारों को बिना तनाव और

लंबी कानूनी प्रक्रिया के सरल एवं सुलभ न्याय प्राप्त होने की आशा जागृत हुई है। जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि राजीनामा, मध्यस्थता और संवाद के माध्यम से कानूनी विवादों का

मानवतापूर्ण समाधान यह दर्शाता है कि जहाँ बातचीत होती है, वहाँ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। लोक अदालतों के माध्यम से साधारण नागरिकों को समय, धन और मानसिक तनाव से न सिर्फ राहत मिलती है, बल्कि न्यायालयों का बोझ भी कम होता है। यही वह समन्वय है जो न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी व जनोन्मुखी बनाता है। जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने आगे कहा कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य प्रकरणों का शीघ्र, सरल, सुलभ और न्यायपूर्ण समाधान करना है। मध्यस्थता के माध्यम से यदि दो पक्षकार फिर से एक-दूसरे के साथ विश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यही लोक अदालत की सर्वोच्च सफलता है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्याय, करुणा, सहअस्तित्व और सामाजिक समरसता की उस भावना का प्रतीक है, जो एक स्वस्थ समाज का आधार बनाती है। जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने आगे बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण पर पूरी कोर्ट फीस वापस प्राप्त हो जाती है और विवादों का प्रेम और सौहार्दपूर्वक अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है

एवं बाद में उसकी कोई अपील रिवीजन नहीं होती है। नेशनल लोक अदालतों में बैंक, विद्युत और नगर परिषद, पालिका व नगर निगम के वसूली राशि से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का भी आपसी राजीनामा से निराकरण होता है और उनमें संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाती है। तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के तत्वावधान में अधिवक्ता संघ के सहयोग से इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में जिस भी अधिवक्ता के द्वारा सर्वाधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाएगा, उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाने का भी निश्चय किया गया है। जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने समस्त पक्षकारों से यह विनम्र अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत की पुनीत भावना और पावन उद्देश्य को सफल बनाते हुए न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में आपसी समझौता कर प्रकरणों का प्रेम एवं सौहार्द पूर्वक अंतिम निराकरण कराते हुए संपूर्ण कोर्ट फीस वापस प्राप्त कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सहभागी बनें।

केट का वो शैक्षणिक दूर : ताकि टीम उड़न छू खबर लिखने से बचे

कीर्ति राणा

इंदौर। ये ऐतिहासिक फोटो इसलिये हैं कि इंदौर में स्थापित राजा रमना सेंटर फार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (केट) का अवलोकन और केन्द्र के तत्कालीन निदेशक डीडी भवालकर से इस सेंटर के कार्यों को पहली बार किसी अखबार के पत्रकारों ने शैक्षणिक दूर में समझा था। तब मैं सिटी चीफ था, केट के हिंदी अधिकारी (नाम याद नहीं आ रहा है) प्रेस नोट लेकर आते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि भास्कर की टीम शैक्षणिक दूर करना चाहती है। उन्होंने कहा मैं भवालकर साब से चर्चा कर के बताऊंगा। उनकी सहमति मिलने की सूचना दी तो मैंने कहा हमारी टीम के लंच की भी व्यवस्था कराना होगी। ये बात संभवतः 1988 के दौरान की है। मेरे नेतृत्व में भास्कर टीम के करीब एक दर्जन साथी केट के ही वाहन से सेंटर पर गए। डॉ. भवालकर ने पूरा सेंटर घुमाया और हमारी



जिज्ञासा का समाधान भी किया। 1987 में जब परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इंदौर में उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र शुरू किया गया था, तब डॉ. भवालकर को संस्थापक निदेशक नियुक्त किया गया था। केन्द्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था। 2000 में, जब उनकी वैधानिक सेवानिवृत्ति होने वाली थी, तो सरकार ने उनकी सेवा को दो साल की अवधि के लिए,

अक्टूबर 2002 तक बढ़ा दिया। 2002 में सेवानिवृत्ति के बाद, वे क्वांटलेज में निदेशक के रूप में शामिल हो गए, जो औद्योगिक और चिकित्सा लेजरों का निर्माण करने वाला एक संगठन है। मैंने ऐसे ही शैक्षणिक दूर सिटी टीम के साथ उदयपुर, श्रीगंगानगर, हिमाचल प्रदेश में भी आयोजित किए थे। ऐसे दूर के पोछे मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि सिटी

रिपोर्टर आए दिन जिन बड़े विभागों की खबर लिखते हैं उनके कार्य-गतिविधियों को समझें ताकि भविष्य में इन विभागों की उड़न छू खबर लिखने से पहले सावधानी बरतें। ये दोनों यादगार फोटो उपलब्ध कराने वाले सहकर्मी मांगीलाल चौहान, शाहिद मिर्जा, अखिल हाडिया सहित अन्य साथी भी नजर आ रहे हैं, इनमें से कुछ साथी दिवंगत हो गए हैं।

देपालपुर विधानसभा में विकास को मिलेगी नई गति, महापौर ने किया प्रतिनिधि नियुक्त



विश्वनाथ समाचार.. भारतसिंह तंवर

इंदौर। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को जमीन पर उतारने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सनी धर्मेन्द्र मिश्रा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम के वार्डों में चल रहे विकास एजेंडा को तेजी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रतिनिधि नियुक्ति के बाद अब क्षेत्र में सड़क, स्वच्छता, रोशनाई, पेयजल,

नाली निर्माण, जनसुविधा विस्तार सहित कई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आने की उम्मीद है। सनी धर्मेन्द्र मिश्रा को नियुक्ति को देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों और जनसंपर्क के माध्यम से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। नागरिकों को भरोसा है कि उनकी नियुक्ति से समस्याओं के त्वरित निराकरण में मदद मिलेगी। नगर निगम का लक्ष्य है कि हर नागरिक तक शासन की योजनाएँ बिना किसी बाधा के पहुँचें और क्षेत्र के विकास में आमजन सीधा लाभ प्राप्त करें।

इंदौर में ठेले वालों और निगम टीम के बीच विवाद : रिमूवल कार्रवाई में बिना सूचना सामान हटाया

इंदौर। इंदौर के कनाडिया रोड, बंगाली नगर में नगर निगम की रिमूवल टीम पर फल के ठेले वालों ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। ठेले वालों का कहना है कि रिमूवल अभियान के दौरान निगम कर्मचारियों ने उन्हें रोड और डंडों से मारा, जिससे एक युवक के सिर



में गंभीर चोट लगी। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार रात हुई, जब निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। घटना के बाद नगर निगम की रिमूवल टीम मौके से चली गई। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले में पुलिस जांच कर

रही है। ठेले वालों का आरोप है कि वे रोजाना ठेला लगाकर फल बेचते हैं, लेकिन निगम की टीम ने बिना कारण उनके साथ मारपीट की। पीड़ित युवक के भाई गोलू ने बताया कि कपिल गौड़ के नेतृत्व में पूरी रिमूवल टीम मौके पर आई थी। टीम ने बिना किसी

अनाउंसमेंट के ठेले का सामान फेंकना शुरू कर दिया और फिर उसके भाई शाहरुख को डंडों से मार दिया। इस घटना की शिकायत खजाना थाना में दर्ज कराई गई है। पिछले हफ्ते भी कनाडिया रोड पर ठेला-गुमठी हटाने के दौरान विवाद हुआ था।

कलेक्टर साहब, इधर भी ज़रा ध्यान दीजिए, लाबरिया में जल निगम ठेकेदार द्वारा जल-कर वसूली पर विवाद तेज!

(जितेंद्र चौहान)

लाबरिया। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल-जल योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करना है, लेकिन विकासखंड सरदारपुर की ग्राम पंचायत लाबरिया में यह योजना बहाल होती दिख रही है। एक ओर जहां ग्रामीणों को 4-5 दिनों के अंतराल पर ही पानी मिलता है, वहीं दूसरी ओर जल निगम के ठेकेदार यशपाल शर्मा द्वारा जल-कर वसूली की शिकायतों ने ग्रामीणों में रोष पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पर्याप्त पानी वितरण नहीं होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा जल-कर वसूला जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार जल-कर वसूली का अधिकार पंचायत एवं स्वच्छता समिति के पास है, न कि किसी ठेकेदार के पास। ग्रामीणों ने कई बार 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई, परंतु समस्या जस की तस



बनी हुई है।

प्लांट फेल, टंकी खाली और ग्रामीणों की बढ़ती परेशानी

लाबरिया में नल-जल योजना के



तहत स्थापित पानी सप्लाई प्लांट लंबे समय से पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। ग्रामीणों को कहना है कि-पानी 4-5 दिनों में एक बार आता है फोन करने पर कर्मचारी कभी टंकी खाली होने का बहाना देते हैं कई जगहों पर लीकेज की समस्या बनी हुई है समय कम होने से घरों में पानी पर्याप्त नहीं पहुँच पाता ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि ‘पहले पानी व्यवस्था सुधारी जाए, उसके बाद ही जल-कर वसूली उचित है।’

ग्रामीणों का सवाल- जब पानी समय पर नहीं, तो जल-कर क्यों?

ग्रामीणों का आरोप है कि जल निगम के कुछ उच्च अधिकारी ठेकेदार को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते नियमों के विरुद्ध जाकर जल-कर वसूली की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर ठोस कार्रवाई करता है या फिर फाइलों में ही मामला दबकर रह जाता है?।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

‘ठेकेदार को जल-कर वसूली का अधिकार नहीं है। मेरे संज्ञान में मामला आया है। हो सकता है वाटरमैन की मदद कर रहा हो, परंतु नियमतः वसूली पंचायत/स्वच्छता समिति करती है। मैं इसकी जांच करवाऊँगा।’

– भवानी सिंह भाटी, फील्ड इंजीनियर, जल निगम

‘जब तक पर्याप्त पानी जनता तक नहीं पहुँचता, तब तक जल-कर वसूली नहीं की जा सकती। पानी व्यवस्था सुचारु होने के बाद ही पंचायत जल-कर वसूलेगी।’

– मैनाबाई रमेश ओसारी, सरपंच

‘जनता को पानी की समस्या से लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। लीकेज भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में जल-कर वसूली गलत है। यह पंचायत का कार्य है, ठेकेदार का नहीं। जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी।’

– नारायण मारू भट्ट, उप-सरपंच

‘4-5 दिनों में बिना निश्चित समय के पानी मिलता है। पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, तभी जल-कर देना चाहिए।’

– लक्की टेलर, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष, लाबरिया

‘पानी की व्यवस्था सही नहीं है, कनेक्शन भी सही नहीं बने हैं। ऐसे में जल-कर वसूलना अनुचित है।’

– मदन चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, लाबरिया

कुंभकर्णी नींद में प्रशासन, हादसे का इंतज़ार?

सरदारपुर विकासखंड के गंगातलाई मजरे का मामला पानी से घिरे जर्जर विद्यालय भवन में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल

विश्वनाथ समाचार...
जितेंद्र चौहान

सरदारपुर। तहसील के संकुल केंद्र लाबरिया अंतर्गत आने वाला मजरा गंगातलाई शिक्षा व्यवस्था की बहाल तस्वीर पेश कर रहा है। सरदारपुर-बदनावर मुख्य मार्ग से लगभग छह किलोमीटर दूर स्थित इस बड़े मजरे में प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्षा पहली से पांचवीं तक लगभग 40 छात्र अध्ययनरत हैं। माही मुख्य बांध के समीप होने के कारण विद्यालय भवन वर्षभर पानी से घिरा रहता है। इसके साथ ही भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। छत और दीवारों में दरारें, चारों ओर कीचड़ एवं असुरक्षित वातावरण के बीच बच्चे प्रतिदिन पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पालकों एवं विद्यालय स्टाफ में हर समय किसी बड़े हादसे का भय बना रहता है।

कई बार अवगत कराया, पर नहीं जागा प्रशासन

ग्रामीणों और पालकों ने अनेक बार संबंधित अधिकारियों एवं



कर्मचारियों को भवन की स्थिति से अवगत कराया। संकुल प्राचार्य लाभू चारण को भी बार-बार जानकारी दी गई, परंतु आज तक सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भवन निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद भी न तो राशि आवंटित हुई और न ही निर्माण कार्य शुरू हुआ। जिम्मेदारों के इस दुलमुल रवैये ने प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल खड़े किए हैं।

मजदूर वर्ग के बच्चों का भविष्य जोखिम में

गंगातलाई मजरे में मुख्य रूप से मजदूर वर्ग के परिवार निवासरत हैं। सीमित साधनों के बीच बच्चे शिक्षा के सहारे अपना भविष्य संवारने का प्रयास करते हैं, लेकिन विद्यालय



भवन की दयनीय स्थिति उनके भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रही है। एक ओर सरकार ग्रामीण अंचलों में शिक्षा को मजबूत करने के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर लापरवाही इन प्रयासों को पलीता लगा रही है।

कब जागेगा प्रशासन?

गंगातलाई मजरे के इस

संबंधित अधिकारी का पक्ष

‘यह मामला मेरे संज्ञान में है। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर अवगत करा चुका हूं। दो-तीन माह पूर्व जारी सूची में भवन निर्माण स्वीकृत होना देखा था। परंतु राशि के अभाव में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। शीघ्र ही इस पर ध्यान देकर राशि प्राप्त होते ही निर्माण प्रारंभ कराया जाएगा।’

– भंवर सिंह, बीआरसी सरदारपुर



विद्यालय की जर्जर स्थिति किसी भी समय दुर्घटना को जन्म दे सकती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर नए भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित करे, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार की मंशा तभी सफल मानी जाएगी, जब जमीनी स्तर पर अधिकारी सक्रिय होकर जिम्मेदारी निभाएंगे और बच्चों को सुरक्षित व बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराएंगे।

इंदौर में ‘ऑपरेशन क्लीन’ भी पूरी तरह क्लीन नहीं : कमिश्नर की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट- हाईकोर्ट में इमेज खराब करने वाले टीआई पर कार्रवाई नहीं

इंदौर। इंदौर में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को कार्यभार संभाले लगभग एक साल पूरा होने को है। इस दौरान उन्होंने ‘ऑपरेशन क्लीन’ चलाकर विभाग की छवि सुधारने का अभियान तेज किया। अभियान के तहत दो टीआई का डिमोशन किया गया, जबकि पांच पुलिसकर्मियों को सेवा से हटाकर सख्त संदेश दिया गया। मंगलवार को भी एक कार्यवाहक एसआई सुभाषचंद्र वर्मा



इंद्रमणि पटेल, टीआई

पर कार्रवाई करते हुए पांच वर्ष के लिए डिमोशन करते हुए उसे आरक्षक बनाया गया। इसके विपरीत, विभाग के भीतर यह नाराजगी भी उभर रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक में विभाग की छवि धूमिल करने वाले विवादित टीआई इंद्रमणि पटेल पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कई कर्मचारी इसे लेकर बंद जुबान में असंतोष जाहिर कर रहे हैं। उनका

कहना है कि इंदौर पुलिस की छवि प्रदेश ही नहीं, बाहर तक प्रभावित हुई है, लेकिन संबंधित अधिकारी पर कदम न उठाना कई सवाल खड़े करता है। खासकर तब, जब थाने में कई मामलों में एक जैसे ‘पॉकेट गवाह’ मिलने की बातें भी सामने आईं। कमिश्नर संतोष सिंह ने विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए ‘ऑपरेशन क्लीन’ चलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छा काम

करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि विभाग की छवि खराब करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन के चलते कई पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता, लापरवाही और गैर-हाजिरी के मामलों में दंडित किया गया है। इसी क्रम में विभाग में अब चंदन नगर टीआई को लेकर भी हलचल बढ़ गई है।

सम्पादकीय

भूख से युद्ध के साथ शिक्षा की लौ जलाता अक्षय पात्र

बहरहाल दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की साल 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। महाभारत में एक कथा आती है..जुए में अपना सबकुछ हारने के बाद पांडव वनवास काट रहे हैं..उसी दौरान वे सूर्य की उपासना करते हैं..सूर्य देव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक पात्र देते हैं..उस पात्र की विशेषता है कि उसमें रखा भोजन कभी खत्म ही नहीं होता...वह सदा भरा ही रहता है। अक्षय का अर्थ ही होता है, जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसमें कभी कोई कमी ना हो..कहना न होगा कि इस्कॉन का अक्षय पात्र भी पांडवों के अक्षय पात्र की तरह हो गया है..भूखे, बेसहारा, गरीब, बेघर बुजुर्ग माताओं, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की भूख मिटाने का आज यह बड़ा सहारा बन गया है। साल 2000 में शुरू इस संकल्प ने चौथाई सदी की यात्रा पूरी कर ली है। अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 24 लाख बच्चों को नियमित रूप से उनके स्कूलों में भोजन करा रहा है। साल 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का आदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि खाद्य निगम के गोदामों में काफी मात्रा में अन्न सड़ जाता है। उस अन्न के जरिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह तर्क जंचा और उसके ही आदेश पर समूचे देश के स्कूलों में दोपहर में बना हुआ भोजन देना जरूरी कर दिया गया। इसके पहले केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पोषण योजना की चुने हुए ब्लॉकों में शुरूआत की, जिसके तहत स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराना शुरू हुआ। बाद में इसके तहत बच्चों को मुफ्त चावल दिया जाने लगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब पका हुआ खाना देना अनिवार्य कर दिया गया। अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की शुरूआत के पीछे अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद का भी एक संकल्प कार्य कर रहा है। स्वामी प्रभुपाद पश्चिम बंगाल के मायापुर में भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी खिड़की से देखा, कूड़े में फेंके भोजन को लेकर कुत्ते और कुछ बच्चों में खींचतान चल रही थी। यह कारुणिक दृश्य देखकर प्रभुपाद परेशान हो गए। उन्होंने तब संकल्प लिया कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसकी वजह से उनके आसपास कोई भूखा रहने को मजबूर ना हो सके। इस्कॉन के मंदिरों में यह व्यवस्था अहर्निश अब तक जारी है। उनके यहां भोजन के वक्त कोई भूखा नहीं रहता। बहरहाल दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की साल 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। पहले साल साल इस योजना के तहत बेंगलुरु के पांच स्कूलों के 1,500 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। तब से यह फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है और आज स्थिति यह है कि अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विद्यालयों के करीब चौबीस लाख बच्चों को रोजाना दोपहर का भोजन मुहैया करा रहा है। अक्षय पात्र का उद्देश्य भूख की वजह से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराना और उन्हें शिक्षा हासिल करने में सहयोगी बनना है। शुरूआत में सीमित पैमाने पर काम करने के बाद, संस्था का विस्तार

क्या सच में किस्मत भगवान लिखता है? नहीं—क्योंकि भगवान मासूमों की चीखें, टूटे सपने और हिंसा के निशान नहीं लिखता



लेखक - पवन जैन पदमावत

समाज अक्सर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए एक ही वाक्य का सहारा लेता है। 'जो हुआ, किस्मत में यही लिखा था।' यह वाक्य कितना आसान है कहना, कितना सरल है लिख देना, पर इसके पीछे छिपा कायरपन, जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति और एक मासूम के दर्द के प्रति हमारी संवेदनहीनता कितनी गहरी है, इसका एहसास तब होता है जब एक तीन साल की बच्ची रोते हुए अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी होती है और दुनिया उससे कहलवाती है कि 'यह उसकी किस्मत थी।' अगर सचमुच किस्मत भगवान लिखता, तो क्या वह तीन साल की नन्ही जान की जिंदगी में बलात्कार जैसी क्रूरता लिखता? क्या वह उस बच्ची की मासूम आँखों में हमेशा के लिए डर भर देता जिसे उसने हँसने और खेलते हुए देखने के लिए दुनिया में भेजा था? क्या भगवान इतनी निर्दयता का निर्माता हो सकता है? नहीं। निश्चित रूप से नहीं। क्योंकि भगवान न्याय का प्रतिक है, क्रूरता का नहीं; सृष्टि का रक्षक है, विनाश का नहीं; मासूमों का सहारा है, उनपर अत्याचार करने वाला नहीं। हकीकत यह है कि भगवान किस्मत नहीं लिखता किस्मत वह समाज लिखता है जो अपनी जिम्मेदारियों को टालता है, अपनी आँखें बंद कर लेता है और अपराधी को उसके ही घर की छाया में पनपने देता है। जब कानून कमजोर पड़ता है, जब व्यवस्था से न्याय गायब हो जाता है, जब परिवार बेटों को संस्कार नहीं देता, जब समाज बेटियों की सुरक्षा को भाग्य पर छोड़ देता है, जब अदालतें वर्षों तक सुनवाई टालती हैं, और जब मीडिया एक

घटना को केवल झूठका साधन बनाकर अगले दिन भूल जाता है। तभी एक मासूम की किस्मत बर्बाद होती है। तब यह अपराध भगवान की इच्छा नहीं होता, बल्कि मनुष्य की कायरता और पापों का परिणाम होता है। सोचिए, तीन साल की बच्ची को क्या पता 'किस्मत' क्या होती है? उसे तो यह भी नहीं मालूम कि दुनिया में हिंसा क्या है। वह तो अभी खिलौनों के नाम सीख रही होती है, रंगों को पहचान रही होती है, और तभी कोई हैवान उसकी दुनिया को नर्क बना देता है। यह नर्क भगवान नहीं बनाता यह इंसान बनाता है। भगवान ने तो इस धरती पर हर बच्ची को मुस्कान के साथ भेजा है; लेकिन यह समाज है जिसने उसकी सुरक्षा छीन ली, यह व्यवस्था है जिसने उसके लिए न्याय का रास्ता कठिन बना दिया, और यह इंसान है जिसने उसके जीवन पर हिंसा का दाग लगा दिया। हमारी बड़ी समस्या यह है कि हम अपराध को 'किस्मत' बनाकर स्वीकार कर लेते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हर अत्याचार किसी दैवी योजना का हिस्सा है। यह सोच अपराधी को ताकत देती है, पीड़िता को कमजोर बनाती है और समाज की रीढ़ को खोखला कर देती है। हम भगवान को दोष देकर अपना दायित्व खत्म कर देते हैं। अगर हम हर दरिंदगी को 'भाग्य' कहकर छोड़ते रहेंगे, तो अपराधी कभी डरना नहीं सीखेगा और समाज कभी बदलना नहीं चाहेगा। किस्मत भगवान नहीं लिखता किस्मत वह माहौल लिखता है जिसे इंसान बनाता है। अगर माहौल में अपराध को जगह मिलेगी, न्याय धीमा रहेगा, कानून ढीला रहेगा, समाज चुप रहेगा तो हर बच्ची की किस्मत खतरे में रहेगी। और वही समाज अगर बेटों को संयम सिखाएगा, कानून को कठोर बनाएगा, अपराधियों के लिए दरवाजे बंद करेगा और पीड़िताओं को सम्मान देगा तो वही समाज अपने बच्चों की किस्मत नई दिशा देता है। समस्या की जड़ सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि वह हर व्यक्ति है जो कहता है। 'जो हुआ, उसी की किस्मत थी।' यह वाक्य अपराध का सबसे बड़ा संरक्षण बन गया है। क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ भाग्य है, तब हम न्याय, सुरक्षा, शिक्षा और सुधार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। यही

वजह है कि इस देश की हज़ारों बच्चियाँ आज भी उस दर्द से गुजरती हैं, जिसे समझना भी मुश्किल है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर बच्ची का बलात्कार उसकी किस्मत नहीं उस समाज का प्रतिबिम्ब है जिसमें हम रहते हैं। यह उस कानून की कमजोरी है जिसके सहारे अपराधी बेखौफ घूमते हैं। यह उस मानवीय विफलता की गूँज है जो इंसानियत से बहुत दूर पहुँच चुकी है। यह उस सोच का परिणाम है जिसमें परिवार अपनी बेटियों को सुरक्षा सिखाता है लेकिन बेटों को जिम्मेदारी नहीं सिखाता। जिस दिन समाज यह समझ लेगा कि भगवान केवल जीवन देता है, लेकिन उस जीवन को सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल बनाना इंसान का कर्तव्य है। उस दिन इस देश की बच्चियाँ रोना बंद कर देंगी। जिस दिन लोग 'किस्मत' की ढाल छोड़कर अपराध पर सवाल उठाएँगे, कानून को मजबूत करेंगे और न्याय को प्राथमिकता देंगे उस दिन मासूमों की जिंदगी में उजाला लौटेगा। जिस दिन माता-पिता अपने बेटों को दूसरों का सम्मान करना सिखाएँगे—उस दिन इस देश की बेटियों को रात में घर लौटने से डर नहीं लगेगा। भगवान मासूमों की चीखें नहीं लिखता वे चीखें लिखता है समाज की चुप्पी, व्यवस्था की कमजोरियाँ और इंसान की विकृत सोच। और जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई बच्ची सुरक्षित नहीं हो सकती। अब समय है कि हम भगवान पर आरोप लगाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाएँ। अब समय है कि हम अपनी इस सोच को बदलें कि 'जो हुआ, किस्मत थी।' नहीं जो हुआ, वह हमारी गलती थी, हमारी चूक थी, हमारी लापरवाही थी। और जब समाज अपनी गलती समझने लगेगा, तब वह किस्मत भी बदलना सीख जाएगा। उस दिन हर बच्ची इस विश्वास के साथ बड़ी होगी कि उसकी किस्मत भगवान ने नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज ने लिखी है। जिसमें भय नहीं, सम्मान है; हिंसा नहीं, अधिकार है; और आँसू नहीं, मुस्कान है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया सेल : एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी

मेजर पॉवर बड़ी उपलब्धि तो सुपर पॉवर बनना बड़ी चुनौती

ऑपरेशन सिन्दूर, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती साख, सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी भारत की ताकत बन गई है। भारत के साथ सबसे बड़ी ताकत स्थिर और कड़े निर्णय लेने में भी सक्षम सरकार होना एक सकारात्मक पक्ष है तो दूसरी ओर जेन जेड और उसके बाद की जैनरेशन की बड़ी भूमिका हो गई है। आस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्था द्वारा जारी एशिया पॉवर इंडेक्स 2025 में भारत का मेजर पॉवर का दर्जा हासिल करना इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत शक्तिशाली देशों की कतार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। लोवी द्वारा जारी इंडेक्स में मेजर पॉवर का दर्जा हासिल करने वाला भारत एक मात्र देश है जबकि सुपर पॉवर के रूप में अमेरिका और चीन अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। हालांकि भारत ने मेजर पॉवर का दर्जा हासिल कर लिया है पर सुपर पॉवर का दर्जा

हासिल करने में अभी भारत को लंबा समय और कड़ी मेहनत व प्रयास करने होंगे। दरअसल 8 पेरामीटर्स में 100 में से 70 से अधिक अंक अर्जित करने वाले देश ही सुपर पॉवर की श्रेणी में आते हैं और अमेरिका इसमें 80.5 अंक प्राप्त कर सुपर पॉवर बना हुआ है वहीं चीन भी अमेरिका के पीछे पीछे 73.7 अंकों के साथ दूसरा सुपर पॉवर बना हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है पर फिर भी पहला स्थान का ताज आने वाले सालों में भी छिनता हुआ नहीं लगता है। भारत ने अवश्य जापान को पछाड़ कर तीसरा स्थान बनाया है और 40 अंक प्राप्त कर मेजर पॉवर तो बन ही गया है। 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले देश मेजर पॉवर की श्रेणी में आते हैं और यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत अकेला देश बन गया है। एशिया प्रशांत के 27 देशों से शेष 23 देश मिडिल पॉवर व उससे

नीचे की श्रेणी में हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस इंडेक्स में पहले दस में भी स्थान नहीं बना पाया है। पाकिस्तान सूची में 16 वें स्थान पर रहा है। निश्चित रूप से यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि और इंटरनेशनल जगत में भारत के बढ़ते दबदबे का स्पष्ट संकेत है। ऑपरेशन सिन्दूर और इससे पहले भी जिस तरह से भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की अग्रगामी भूमिका तय की गई है उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों ने इसे तीसरे पायदान पर लाने में खासी भूमिका तय की है। भारत आज दुनिया के देशों में बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और दुनिया के देशों में सबसे अधिक यानी कि विदेशी निवेश में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी द्वारा 2018 से एशिया पॉवर इंडेक्स जारी

करना आरंभ किया है। 2025 में एशिया पॉवर इंडेक्स का सातवां संस्करण जारी किया है। लोवी द्वारा 8 पेरामीटर्स के आधार पर अंक जारी किये जाते हैं। इसमें सैन्य क्षमता, रक्षा नेटवर्क, आर्थिक शक्ति, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध, कूटनीतिक व सांस्कृतिक संबंध, लचीलापन, भविष्य के संसाधन आदि पेरामीटर्स के आधार पर 27 देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन सिन्दूर ने भारत की सैन्य शक्ति और ताकत से दुनिया के देशों को झकझोर कर रख दिया है। सैन्य संसाधनों में आज भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से भारत की इकोनोमी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है उससे दुनिया के देशों में भारत ने अलग ही स्थान अर्जित कर लिया है। भारत में देसी-विदेशी विदेशी निवेश का जिस तरह का माहौल बना है और जिस तेजी से विपरीत

वैश्विक हालातों के बावजूद और यहां तक कि ट्रंप की टैरिफ नीति के बावजूद भारत की अर्थ व्यवस्था व विकास का स्तर लगातार बने रहना बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिन्दूर, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती साख, सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी भारत की ताकत बन गई है। भारत के साथ सबसे बड़ी ताकत स्थिर और कड़े निर्णय लेने में भी सक्षम सरकार होना एक सकारात्मक पक्ष है तो दूसरी ओर जेन जेड और उसके बाद की जैनरेशन की बड़ी भूमिका हो गई है। आज तकनीकी रूप से भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत युवाओं का देश हो गया है। सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, इकोनोमिक क्षमता और प्रौद्योगिकी, डिजिटलाइजेशन, कूटनीतिक और सांस्कृतिक रिलेशन आदि क्षेत्र में भारत ने पिछले साल की तुलना में अधिक अंक अर्जित किये हैं।

जनसरोकारों को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक संगोष्ठी : हातोद में पत्रकारिता के मूल्यों पर सार्थक मंथन

विश्वनाथ समाचार... जीवन डोडिया

हातोद। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र ने हाल ही में पत्रकारिता जगत के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय दर्ज किया, जिसने स्थानीय पत्रकारिता को नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए संकल्पों से भर दिया। हातोद स्थित विश्राम गृह में आयोजित देपालपुर प्रेस क्लब का भव्य सम्मेलन न केवल एक औपचारिक मिलन रहा, बल्कि यह सत्य, साहस और संघर्ष जैसे पत्रकारिता के शाश्वत मूल्यों को पुनर्संस्थापित करने वाला मंच साबित हुआ। मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ हुए इस आयोजन में वरिष्ठ पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक अग्रजों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। पत्रकार जीतेंद्र (जीतू) सोनी, योगेंद्र जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवणसिंह चावड़ा, इंदौर भाजपा नगर उपाध्यक्ष



भूपेंद्रसिंह केसरी, हातोद तहसीलदार लोकेश आहूजा, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार शिंदे, समाजसेवी सत्यनारायण आजाद सहित अनेक विशिष्ट अतिथि इस मिलन समारोह का हिस्सा बने। देपालपुर प्रेस क्लब हातोद इकाई ने पारंपरिक आदर-सम्मान के अनुरूप अतिथियों को मोतियों की माला, दुपट्टा और शील्ड भेंट की।

निष्पक्ष पत्रकारिता पर गहन चिंतन

मुख्य अतिथि जीतू सोनी ने आज के दौर में पत्रकारिता की चुनौतियों पर बेबाकी से बात करते हुए कहा कि- ‘सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसकी जीत



निश्चित है। एविडेंस आधारित पत्रकारिता किसी भी दबाव से कहीं बड़ी होती है।’ वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र जोशी ने भी प्रमाणिक तथ्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि पत्रकार के पास मजबूत साक्ष्य हैं, तो किसी भी दबाव, धमकी या प्रभाव से डिगने की आवश्यकता नहीं। इंदौर भाजपा नगर उपाध्यक्ष भूपेंद्रसिंह केसरी ने वर्तमान मीडिया पर उठ रहे सवालों को ध्यान में रखते हुए कहा कि खबरों की विश्वसनीयता आज सबसे बड़ी कसौटी बन गई है, क्योंकि तेजी से फैलती सूचनाओं के बीच तथ्य अक्सर शाम तक बदल जाते हैं।

ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियाँ भी आई सामने

वरिष्ठ समाजसेवी सत्यनारायण आजाद ने ग्रामीण पत्रकारों की वास्तविक समस्याओं को बेहद मार्मिकता से रखा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, पहुँच की कठिनाई और कार्यस्थलों पर सुरक्षा-जिम्मेदारी का अभाव, इन पत्रकारों को कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों में काम करने को बाध्य करता है। उन्होंने संगठन से आग्रह किया कि ग्रामीण पत्रकारों की आवाज को प्राथमिकता के साथ उठाया जाए।

प्रशासनिक सहयोग का स्पष्ट आश्वासन

कार्यक्रम में हातोद तहसीलदार लोकेश आहूजा ने पत्रकारों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने कहा- ‘आज पत्रकार सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। सूचना जुटाने, फीलड में रिपोर्टिंग और सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।’ उन्होंने यह भी कहा कि यदि पत्रकार किसी दबाव, परेशानी या अनावश्यक अवरोध का सामना करते हैं, तो वे सीधे प्रशासन से संपर्क करें।

संगठन को नई दिशा: नई कार्यकारिणी का गठन

कार्यक्रम के दौरान देपालपुर प्रेस क्लब हातोद इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई- अध्यक्ष : पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा, संरक्षक : अभिजीत राठौर, मार्गदर्शक : वरिष्ठ पत्रकार अरुण जैन, सचिव : राजू पाल

मुख्य प्रेस क्लब अध्यक्ष संदीप सेन ने नई टीम को जिम्मेदारी सौंपकर संगठन को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। इसी अवसर पर बेटमा इकाई द्वारा मुख्य अतिथि जीतू भाई सोनी का जन्मदिन भी हर्षोल्लास से मनाया गया, जिससे कार्यक्रम में सौहार्द और उत्साह का रंग और गहरा हो गया।

एक संगोष्ठी जो यादों में दर्ज रहेगी

इस आयोजन में देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा सहित पूरे क्षेत्र के पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। यह सम्मेलन केवल पत्रकारों की समस्याओं को सुनने और समझने का मंच ही नहीं रहा, बल्कि इसने पत्रकारिता के भावी स्वरूप, चुनौतियों के समाधान, और संगठन की मजबूती पर भी नई सोच को जन्म दिया। हातोद की यह ऐतिहासिक पत्रकार संगोष्ठी आने वाले समय में क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी।

सुधार की मिसाल बना सब जेल देपालपुर: बंदियों के लिए आरओ प्लांट, आर्गेनिक सब्जियां, योग, हेल्थ कैंप और हरित परिसर की अनोखी पहल; कारागार प्रबंधन ने प्रदेश में स्थापित किया नया मॉडल

विश्वनाथ समाचार... अजय जैन

देपालपुर। सब जेल देपालपुर में बंदियों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य व सुधार की दिशा में शुरू की गई अभिनव एवं तकनीकी पहलों ने जेल प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित कर दिया है। बंदियों की बुनियादी आवश्यकताओं, स्वच्छ पेयजल, पोषक भोजन, मानसिक स्वास्थ्य तथा सकारात्मक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए जेल विभाग द्वारा आरओ शुद्ध पेयजल प्लांट स्थापित किया गया है। यह सुविधा करीब डेढ़ वर्ष पूर्व भेजे गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप संभव हुई है। ज्ञात हो कि सब जेल देपालपुर के उप अधीक्षक रामसहाय कुशवाह ने विभाग को तकनीकी मानकों और स्वास्थ्य संरक्षण से जुड़ा विस्तृत प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति प्रदान करते हुए विभाग द्वारा मशीन की स्थापना करवाई गई। आरओ प्लांट की स्थापना के साथ अब बंदियों को प्रतिदिन प्रमाणित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता, स्वास्थ्य स्तर और समग्र सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा।

मॉडल कारावास प्रबंधन: जेल परिसर में ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन

उप अधीक्षक रामसहाय कुशवाह के प्रबंधन कौशल और सुधारात्मक कार्य योजनाओं के अंतर्गत जेल परिसर में ऑर्गेनिक मॉडल के आधार पर सब्जियों की खेती करवाई जा रही है। यह कदम न केवल ताजी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि बंदियों को श्रम, आत्मनिर्भरता, कृषि-जागरूकता और सकारात्मकता से भी जोड़ रहा है। सब्जी उत्पादन के कारण बंदियों को बाजार-निर्भर खाद्य



व्यवस्था से अलग होकर प्रतिदिन ताजा, पोषक और रसायन-मुक्त सब्जियाँ उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस – योग और हेल्थ चेकअप कैंप

जेल प्रबंधन ने बंदियों के शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से प्रतिदिन सामूहिक योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनसे तनाव नियंत्रण, अनुशासन, ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही सप्ताह में दो दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें चिकित्सकों द्वारा नियमित जांच, मेडिकल परामर्श, उपचार तथा आवश्यक औषधि वितरण किया जाता है। यह पहल कारागार सुधार के आधुनिक मानकों – हेल्थ केयर, माइंड केयर और बिहेवियरल करेक्शन – पर आधारित मानी जा रही है।

हरियाली, स्वच्छ वातावरण व पॉजिटिव माइंड सेट की दिशा में कदम

जेल परिसर में हॉर्टिकल्चर एवं



लैंडस्केपिंग आधारित सफाई और हरियाली पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पौधारोपण, बगीचे और नियमित सफाई व्यवस्था की बंदौलत परिसर में स्वच्छ, शांत और अनुशासित वातावरण स्थापित हुआ है। यह पहल बंदियों में प्रकृति के प्रति जुड़ाव और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने की सराहना – प्रदेश के लिए नए मॉडल की संभावना

सब जेल देपालपुर में लागू की गई इन सुधारात्मक योजनाओं और तकनीकी क्रियान्वयन ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रभावित किया है। केंद्रीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर, एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी एवं जिला न्यायाधीश हिदायतउल्ला खान ने उप अधीक्षक रामसहाय कुशवाह की कार्यप्रणाली को उत्कृष्ट, प्रेरणादायक और अनुकरणीय बताया है। अधिकारियों का मत है कि देपालपुर मॉडल भविष्य में प्रदेश के अन्य कारागारों के लिए भी सुदृढ़ सुधार मॉडल साबित हो सकता है।

दंड नहीं, परिवर्तन आधारित कारावास प्रणाली की प्रेरक मिसाल

देपालपुर सब जेल में चल



रही पहलें यह संदेश दे रही हैं कि कारावास का उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं बल्कि व्यवहार-सुधार, स्वास्थ्य संरक्षण और सामाजिक पुनर्स्थापन होना चाहिए। आरओ प्लांट, ऑर्गेनिक फूड मॉडल, योग प्रशिक्षण, हेल्थ कैंप और ग्रीन कैंपस जैसे प्रयास न केवल बंदियों के स्वास्थ्य और जीवनशैली को उन्नत बना रहे हैं, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन और पुनर्वास को भी गति दे रहे हैं। देपालपुर सब जेल वर्तमान में प्रदेश की सुधारात्मक जेल व्यवस्था का सबसे सशक्त और प्रभावशाली उदाहरण बनकर सामने आया है।

सब जेल देपालपुर में धार्मिक गतिविधियों से बड़ा सकारात्मक वातावरण

सब जेल देपालपुर में सुधारात्मक पहलों के साथ आध्यात्मिक गतिविधियाँ भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। प्रतिदिन सुबह सामूहिक गीता पाठ कराया जाता है, जिससे बंदियों में अनुशासन, आत्मबल और मानसिक शांति विकसित हो रही है। वहीं हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाकर विशेष श्रृंगार किया जाता है तथा सामूहिक सुंदरकांड पाठ संपन्न होता है। इन आयोजनों से जेल परिसर में भक्ति, शांति व सकारात्मकता का माहौल और अधिक सुदृढ़ हो गया है।

पत्रिका में राहु का महत्व और पितृ दोष का गूढ़ ज्योतिषीय विश्लेषण

भारतीय वैदिक ज्योतिष में राहु को एक अत्यंत प्रभावशाली छाया ग्रह माना गया है। यह ग्रह भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता, परंतु जन्मकुंडली के गहन अध्ययन में इसका महत्व सबसे निर्णायक रूप में सामने आता है। राहु जीवन में उन अदृश्य शक्तियों, कर्मजन्य प्रभावों और पूर्वजों के संबंधों को दर्शाता है, जिन्हें सामान्यतः मानव आँखों से समझ पाना संभव नहीं होता।

ज्योतिष के अनुसार नौ ग्रहों में से सात ग्रह भौतिक रूप से दृश्य हैं, जबकि राहु और केतु अदृश्य बिंदु हैं, जिन्हें चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं के प्रतिच्छेदन से निर्मित माना जाता है। यही अदृश्यता इन्हें रहस्यमय और शक्तिशाली ग्रह बनाती है। राहु विशेष रूप से उस अदृश्य जगत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रेतलोक कहा गया है, जहाँ वे आत्माएँ रहती हैं जिन्हें अकाल मृत्यु, बाधित आयु या अपूर्ण इच्छाओं के कारण मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए राहु को पितृ ऊर्जा, पूर्वजों के संकेत और वंशानुगत कर्मों का प्रबल कारक माना गया है।

यदि परिवार में किसी प्रकार का गर्भपात, असामयिक मृत्यु, दुर्घटना जनित मृत्यु या अचानक जीवन समाप्त होने जैसी घटनाएँ घट चुकी हों, तो उन आत्माओं के अपूर्ण कर्म और इच्छाएँ परिवार की आने वाली पीढ़ियों पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालती हैं। इसी ऊर्जा को जन्मकुंडली में पितृ दोष कहा जाता है। पितृ दोष की पहचान मुख्यतः राहु और केतु की स्थिति, उनकी दृष्टि और उनके द्वारा पीड़ित ग्रहों के माध्यम से की जाती है।

विशेषकर नवम भाव (पितृ भाव), सूर्य (पितरों का कारक) और अष्टम भाव (अदृश्य शक्तियों का स्थान) पर राहु का प्रभाव पितृ दोष के प्रमुख संकेत माने जाते हैं।

पितृ दोष के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से प्रकट होते हैं—जैसे संतान प्राप्ति में विलंब, आर्थिक रुकावटें, परिवार में कलह, अचानक बाधाएँ, निर्णयों में असफलता, और कभी-कभी सपनों में पूर्वजों का संकेत मिलना भी। यह दोष केवल ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सूक्ष्म ऊर्जा है जो व्यक्ति को सुधार, सेवा, दान और कर्म सुधार की दिशा में प्रेरित करती है।

पितृ दोष शांति का प्रथम और सर्वाधिक प्रभावी उपाय गंगा स्नान और पितृ तर्पण माना गया है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए ही गंगा माता को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। इसीलिए गंगा जल को पितरों की शांति का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। इसके बाद जन्मकुंडली में राहु-केतु की स्थिति के अनुसार शांति कर्म, मंत्र जाप, दान और पूजा की जाती है।

राहु का सही अध्ययन व्यक्ति के जीवन की अदृश्य दिशाओं को खोलता है—कहीं राहु अचानक उन्नति देता है, कहीं भ्रम पैदा करता है, कहीं व्यक्ति को असाधारण बुद्धि देता है तो कहीं उसे भटकाव की ओर ले जा सकता है। इसलिए ज्योतिषीय विश्लेषण में राहु को विशेष महत्व दिया जाता है। यह केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि उन शक्तियों का प्रतिनिधि है जो व्यक्ति के कर्म, पूर्वजों, और नियति के बीच एक सूक्ष्म पुल का कार्य करती हैं।

दीपक जायसवाल
(ग्रहों के डॉक्टर)
ग्रह दोष निवारण विशेषज्ञ
वास्तु विशेषज्ञ
स्थान ऊर्जा विशेषज्ञ

मालवा के वीर सपुत महाराव बख्तावर सिंह राठौड़ के बलिदान और शौर्य का इतिहास
मालवा वासियों के दिलों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है उनका त्याग और संघर्ष हर युवा हर भारतवासी
के लिए आदर्श होना चाहिए

देश की स्वतंत्रता के लिए 1857 में अपने प्राण
की आहुति देने वाले वीरों के वीर

अमर शहीद महाराव बख्तावर सिंह राठौड़

अमझोरा राज्य

अमझोरा नरेश महाराव बख्तावर सिंह राठौड़
की 201 वी जन्म जयंती की

कनक ग्राफिक्स, अमझोरा

हार्दिक शुभकामनाएं
ग्राम पंचायत एवं
समस्त पंचगण

विनीत - समस्त ग्रामवासी, अमझोरा

14 दिसम्बर सन् 1824 अमझेरा के राठौड़ राजवंश के कुल दीपक एवं राजकुमार के रूप में

-महाराजा राव
अजीतसिंहजी माता
महारानी भटियाणीजी
इन्द्रकंवर



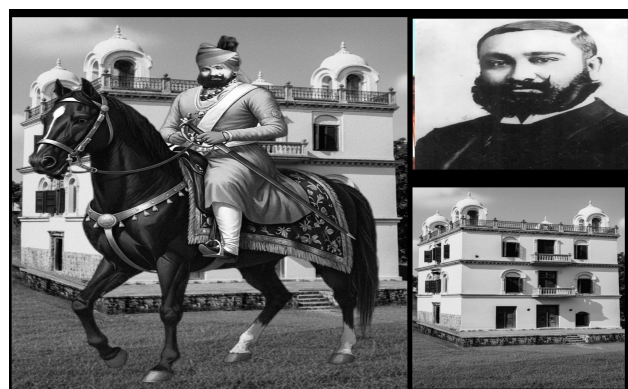
राज्याभिषेक 21 दिसम्बर 1831 को (सात वर्ष की अल्पायु में) पिता महाराजा अजीतसिंहजी के निधन के होने पर । अंग्रेजों पर पहला आक्रमण 02 जुलाई 1857 की रात्रि में भोपावर छावनी पर हमला करके अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया एवं भोपावर छावनी पर कब्जा करके सारा धन व हथियार लूट कर भोपावर छावनी में आग लगा दी । अंग्रेजों पर दूसरा



आक्रमण 10 अक्टूबर 1857 को अंग्रेजों की भोपावर छावनी पर पुनः हमला करके छावनी कब्जे में कर ली व 11 अक्टूबर को मालवा भील पल्टन के सैनिक मुख्यालय सरदारपुर पर भी भीषण हमला करके तीन घंटे की घमासान लड़ाई के बाद अंग्रेजों की सरदारपुर छावनी पर भी कब्जा कर लिया । अंग्रेजों पर तीसरा आक्रमण 16 अक्टूबर 1857 को मानपुर-गुजरी ब्रिटिश सैन्य छावनी पर कब्जा करके कमांडर कर्नल लिडरले एवं विशेष तोपों के साथ तैनात कैप्टन केन्टीज एवं अश्वारोही सेना के प्रभारी जनरल क्लार्क को पराजित कर सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया ।

अंग्रेजों पर चौथा आक्रमण 18 अक्टूबर 1857 को मण्डलेश्वर छावनी पर चौतरफा आक्रमण

करके मण्डलेश्वर छावनी पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारियों के सम्मुख हथियार डालकर कैप्टन केप्टीज एवं जनरल क्लार्क महु भाग निकले। गिरफ्तारी संधिवाता के बहाने धोखे से अमझोरा राज्य के लालगढ़ किले से बुलवाकर तिरला के पास दिनांक 11 नवम्बर 1857 को महाराजा बख्तावरसिंहजी को गिरफ्तार कर दिनांक 13 नवम्बर 1857 को महु जेल में डाल दिया। सजा 21 दिसम्बर 1857 को झूठे मुकदमें में फंसाकर अंग्रेज अधिकारियों ने फांसी की सजा सुना दी। ज्ञातव्य है कि ब्रिटिश सेना के ए.जी.जी. राबर्ट हेमिल्टन ने महाराजा बख्तावरसिंहजी को असीरागढ़ के किले में कैद की सजा सुना दी थी लेकिन बाद में किन परिस्थितियों के दबाव में आकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई? यह खोज का विषय है जो फांसी 10 फरवरी 1858 को प्रातः नौ बजे इन्दौर में सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया तो फांसी का



फन्दा महाराजा बख्तावरसिंहजी का भार नहीं सहन कर सका और टूट गया। दोबारा पुनः मोटी रस्सी का फन्दा बनाया गया, जिसे महाराजा ने स्वयं अपने हाथों से गले में डालकर मौत का वरण कर लिया। अंग्रेजों ने दिन भर महाराजा बख्तावरसिंहजी की लाश को फाँसी के फन्दे पर लटकाये रखा। और इस तरह अमझोरा का यह वीर भारतमाता की आजादी की बलिवेदी पर अमर शहीद हो गया।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सम्पूर्ण भारत में मालवा क्षेत्र की एक छोटी सी रियासत अमड़ौरा ही ऐसी रियासत थी जिसके समक्ष न तो दिल्ली के बादशाह की बादशाहत पेशवा की पेशवायी और महारानी झाँसी की सत्ता खो जाने जैसा कोई भय था

तथा न ही अंग्रेजों ने अमझेरा के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की थी। केवल भारतमाता को विदेशी परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने की टीस ही इस युवा राजा को उद्धेलित किये जा रही थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमझेरा के राजा बख्तावरसिंह ही एकमात्र ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने निःस्वार्थ भाव से एकमात्र भारतमाता को दासता की बेड़ियों से मुक्त करवाने के उद्देश्य से ही अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, लेकिन चाटुकार इतिहासज्ञों ने इस तथ्य को अभी तक जनता से क्यों छुपाये रखा? यह शोध का विषय है। भारतीय इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमझेरा के राजा बख्तावरसिंहजी राठौर को वह सम्मान नहीं दे सके, जिसके वे हकदार हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि हमारा इतिहास हमेशा सम्प्रादों, बादशाहों, शहानशाहों, और बड़े-बड़े महाराजाओं के इर्द-गिर्द अधिक घमटा नजर आता है।

बख्तावरसिंहजी एक छोटी सी रियासत के राजा थे और राजा के संगी साथी और प्रजा मूल रूप से किसान और भील-भीलाल (वनवासी) थे, अतः छोटे लोगों की कुर्बानी और जीवन शैली का विश्लेषण इतिहास से सदैव नदारद होते आया है। यह भारत का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है ? ज्ञातव्य है कि अमझेरा के अमर शहीद महाराजा बख्तावरसिंहजी ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एकमात्र ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों ने राजा होने के बाद भी सरेआम फांसी पर लटकाया और मरणोपरांत उनकी पार्थिव देह को भी दिन भर फांसी पर लटकाये रखा ।

आजादी के 75 वर्षों के दौरान अमझेरा के इस रणबांकुरे की एक मात्र निशानी अमझेरा का किला प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार होकर पूर्णतः खण्डहर में तब्दील हो चुका है। अमझेरा के अमर शहीदों की स्मृतियों को चिर-अक्षुण्ण रखने के लिये अमझेरा में एक भव्य शहीद स्मारक निर्माण की अत्यावश्यकता है। प्रशासनिक स्तर पर अमझेरा के विकास हेतु पहल की जाना अमझेरा के अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इंदौर। शहर में बेतरतीब चल रहे ई-रिक्शा और उनके कारण बिगड़ते ट्रैफिक को सुधारने के लिए प्रशासन ने नया प्लान तैयार किया है। अब पूरे इंदौर को छह अलग-अलग रूट (जोन) में बांटा जाएगा। हर रूट का अलग रंग (कलर कोड) तय होगा। इस रंग का लोगो ई-रिक्शा के आगे और पीछे लगाया जाएगा। हर रूट लगभग 12 से 15 किमी का होगा। चालक अपनी पसंद का जोन चुन सकेगा और उसे सिर्फ उसी जोन में गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे रूट में पाए जाने पर उस पर कार्रवाई होगी। ई-रिक्शा संचालन को ठीक करने को लेकर आरटीओ प्रदीप शर्मा और ट्रैफिक डीसीपी आनंद कलादगी ने ई-रिक्शा संचालकों के साथ बैठक की। जिला सड़क सुरक्षा समिति की पिछली बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। कलेक्टर ने परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को मिलकर प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। शहर को छह जोन में बांटा जाएगा। हर जोन की सीमा तय होगी। चालक उसी जोन में



सवारी बैठा और छोड़ सकेगा। हर रूट के लिए अलग रंग तय किया जाएगा। जैसे यदि रूट-1 का रंग पीला है, तो उस रूट के सभी ई-रिक्शा पर पीला लोगो लगाया जाएगा, जिस पर रूट नंबर, रिक्शा नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा।

रूट निर्धारण राजबाड़ा को केन्द्र में रखकर किया जा रहा है। दो रूट पश्चिम इंदौर में। दो पूर्वी इंदौर में। और दो रिंग रोड व

आस-पास के क्षेत्र में बनाए जाएंगे। अपने तय रूट से बाहर चलने वाले ई-रिक्षा पर चालान होगा। अभी इंदौर में करीब 10 हजार ई-रिक्षा चल रहे हैं। राजवाड़ा, पाटनीपुरा, भंवरकुआं और गंगवाल जैसे क्षेत्रों में ये सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को प्रभावित करते हैं। नई व्यवस्था से इस अव्यवस्था पर रोक लगने की उम्मीद है। ऑटो रिक्षा चालक महासंघ के अनुसार अब ई-रिक्षा चालकों को वर्दी पहनना और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। आगे चलकर इनके लिए स्टैंड भी बनाए जाएंगे।



बकवाँ गांव : चार पीढ़ियों से नर्मदेश्वर शिवलिंग निर्माण की अद्वितीय परंपरा, विश्वस्तरीय शिल्प का केंद्र

इन्दौर। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से 50 किलोमीटर, कसरावद एवं सनावद से 35 किलोमीटर दूर स्थित बकवाँ गांव आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट शिल्पपरंपरा के कारण पहचान बना चुका है। यह भारत का एकमात्र स्थान है, जहां पीढ़ियों से नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण निरंतर किया जा रहा है। आजादी से पहले आरंभ हुई यह परंपरा अब चौथी पीढ़ी तक जीवंत है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान कर रही है।

परंपरा के जनक : स्वर्गीय मांगीलाल नामदेव

नर्मदेश्वर शिवलिंग निर्माण कार्य की नींव बकवाँ गांव के प्रख्यात शिल्पकार स्व. मांगीलाल नामदेव ने रखी थी। 2006 में उनके स्वर्गवास तक वे इस कला को निखारते रहे और गांव के लगभग 200 परिवारों को यह विशेष कौशल सिखाया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप आज गांव के करीब 350 परिवार उसी कला के सहारे जीवन-यापन कर रहे हैं। यह मॉडल ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है।



चार पीढ़ियों का निरंतर योगदान

मांगीलाल नामदेव के बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया- उनके पुत्र दीपक कुमार नामदेव, भाई शिवनारायण नामदेव, और फिर अगली पीढ़ी के सुशील, हेमंत और हितेश नामदेव ने। अब चौथी पीढ़ी के युवा सक्षम नामदेव भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिससे यह कला आधुनिक समय में नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त कर रही है।

नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन : गांव की पहचान

आज बकवाँ गांव की यह परंपरा एक संगठित रूप में 'नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन' संस्था के नाम से जानी जाती है। इस संस्था में



लगभग 150 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, जो देश-विदेश में भेजे जाने वाले शिवलिंगों को तलाशने, नक्काशी और परिष्करण जैसे कार्यों



में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक पहचान तक

स्वर्गीय मांगीलाल नामदेव की कला को उस समय राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नर्मदेश्वर शिवलिंग भेंट किया। इसके बाद यह शिल्प विदेशों में भी प्रशंसा का विषय बना और बकवाँ गांव की प्रतिष्ठा वैश्विक मंच पर स्थापित हुई।

विश्व का सबसे विशाल नर्मदेश्वर शिवलिंग

इस परंपरा की सबसे

उल्लेखनीय उपलब्धि वह भव्य शिवलिंग है जिसकी- ऊंचाई: 24 फीट वजन: 66 टन यह अद्वितीय शिवलिंग नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन द्वारा निर्मित किया गया और आज हैदराबाद में स्थापित है। यह भारत में शिल्पकला की गहराई, तकनीकी दक्षता और आध्यात्मिक परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

बकवाँ गांव : सांस्कृतिक धरोहर और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल

नर्मदेश्वर शिवलिंग का घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता महत्व बकवाँ गांव को न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि यह गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पारंपरिक कौशल संरक्षण और हस्तशिल्प आधारित उद्योग के रूप में एक राष्ट्रीय मॉडल भी प्रस्तुत करता है। चार पीढ़ियों से जीवित यह परंपरा आज भी निरंतर विस्तार कर रही है और बकवाँ गांव को अध्यात्म, शिल्प और तकनीक का संगम बनाकर देश-दुनिया में पहचान दिला रही है।

जनसुनवाई में कलेक्टर वर्मा द्वारा आवेदकों को तत्काल राहत

इन्दौर। कलेक्टर कार्यालय इंदौर में आज कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की विशेष उपस्थिति में जनसुनवाई सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में 285 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अनेक का हाथों-हाथ निराकरण किया गया। जिन आवेदनों पर तत्काल निर्णय संभव नहीं था, उनके लिए कलेक्टर श्री वर्मा ने समय-सीमा निर्धारित की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा इनकी साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। जनसुनवाई में भरण-पोषण, आर्थिक सहायता, राजस्व, पुलिस,



स्वास्थ्य एवं सामाजिक विवादों सहित विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए। जहां तत्काल सहायता संभव थी, वहां स्वास्थ्य जांच, आर्थिक सहायता

उपलब्ध कराने और अन्य आवश्यक कार्यवाही उसी समय की गई। जनसुनवाई के दौरान बालिका याशिका को शिक्षा के लिए मदद दी

गई। वहीं सविंद नगर निवासी अंबिका वर्मा ने परिजनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने व संपत्ति संरक्षण की मांग की। कलेक्टर श्री वर्मा ने यह प्रकरण मध्यस्थता केंद्र को सौंपते हुए इसके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसी प्रकार विसवीर सिंह की बालिका के जटिल इलाज हेतु 40 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। एक दिव्यांग युवती को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई तथा दिव्यांग शकुन्ता बाई को रेड क्रॉस से सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर रोजगार हेतु सहयोग प्रदान किया गया।

आबकारी इंदौर की अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

इन्दौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेश पर आबकारी टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। आज की कार्यवाही में शंका के आधार पर एक दोपहिया वाहन को रोककर उसके आगे के स्पेस में रखे दो पेटियों को खोलकर उसकी तलाशी लेने पर उसमें एक पेटी में 50 पाव देशी मदिरा प्लेन व दूसरी पेटी में 12 बोतल लण्डन प्राईड विदेशी मदिरा पायी गई। अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही मदिरा जप्त कर आरोपी विपुल पिता श्री रामलाल तिवारी निवासी- मच्छी बाजार, इंदौर को रोग हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जप्त मदिरा और वाहन की कीमत 76910 रुपए आंकी गई है।



प्रदेश के 55 हजार ग्रामों में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का नेटवर्क खड़ा किया जायेगा : नागर

इन्दौर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा) श्री मोहन नागर ने कहा है कि प्रदेश के 55 हजार ग्रामों में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का नेटवर्क खड़ा किया जायेगा। श्री नागर मंगलवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में इंदौर जिले के नवांकुर संस्थाओं, प्रस्फुटन समितियों एवं मेंटर्स की जिला स्तरीय संवाद बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। संवाद बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और देवी अहिल्या माता की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुआ। बैठक के दौरान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर

द्वारा जिले के नेटवर्क से संवाद किया गया। उनके द्वारा नवांकुर, मेंटर्स और प्रस्फुटन समितियों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया गया कि आगामी समय में परिषद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में समस्त 55 हजार ग्रामों में ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का नेटवर्क खड़ा करेगी। यह प्रस्फुटन समितियां स्वैच्छिकता और स्वालंबन के आधार पर समग्र ग्राम विकास को लेकर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड में चिन्हांकित आदर्श ग्राम में संस्कार केंद्र, नर्सरी की स्थापना,

पुस्तकालय, गौपालन आदि विषयों में कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत मेंटर्स और विद्यार्थियों के माध्यम से प्रयोगशाला ग्रामों में सामुदायिक नेतृत्व खड़ा किया जाएगा। उन्होंने परिषद की आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी समय में युवा जन अभियान, नवांकुर सखी अभियान, जल संचय अभियान, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ समुदाय विकास कार्यक्रम, स्वदेशी मेलों आदि कार्यक्रमों के माध्यम से परिषद के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा।

आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में अपर मिशन संचालक सरियाम ने ली बैठक

इन्दौर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अपर मिशन संचालक श्री मनोज कुमार सरियाम (आईएएस) की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में मंगलवार को इंदौर में बैठक सम्पन्न हुई। उल्लेखनीय है कि श्री मनोज कुमार सरियाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए इंदौर जिले के ओआईसी हैं। श्री सरियाम ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में योजनाओं के क्रियान्वयन में जनसंख्या वातावरण एवं नवाचारों का भी ध्यान रखा जाये। इंटीग्रेटेड अप्रोच पर ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि इंदौर



जिला अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कुछ कार्यक्रमों में उपलब्धि बहुत अच्छी है, किन्तु मेरी अपेक्षा यह है कि सीएम हेल्पलाइन, शिशु

एवं मातृ स्वास्थ्य संचारी एवं गैर संचारी रोगों में और बेहतर परिणाम देना है। जन भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।